(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ऐसे कितने लघु उद्योग हैं जो केन्द्रीय सहायता से चलाए जा रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके उत्पादन और निर्यात आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उनके विस्तार, आधुनिकीकरण और उनके द्वारा नई प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता/अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत् लघु उद्योग सेवा संस्थानों के माध्यम से अधिक चुने स्थानों/समूहों के विशिष्ट अध्ययन करके आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन का एक पुनः अभिमुख कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में लगभग 25 समूह अध्ययन करने का प्रस्ताव है ।

प्रौद्योगिकियों के विकास तथा उन्हें अपनाने के लिए सरकार ने लघु उद्योगों के लाभ के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र और विशिष्ट संस्थान स्थापित किए हैं ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सहायता से कोई लघु एकक नहीं चलाया जा रहा है ।

गुजरात में खादी ग्रामोद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

658. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गुजरात में खादी ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ।

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकासार्थ नयी योजनाओं सहित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) द्वारा किया जाता है । राज्य बोर्ड के साथ हुई अपनी बजट चर्चाओं के अनुसार सहमति प्राप्त कार्यक्रमों के आधार पर के. वी. आई. सी. अनुदान और ऋण के रूप में गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । के. वी. आई. सी. ने गुजरात सहित देश के पहाड़ी, सीमावर्ती, जनजातीय क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के लिए भी वित्तीय सहायता की योजनाएं और प्रतिमान तैयार किए थे ।

खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दी गयी धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

	दी गयी धनराशि	
	अनुदान	ऋण
खादी	400.15	59.51
ग्रामोद्योग	31.56	58.91
योग	431.71	118.45

Closing down of Sick PSU

659 SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Union Government propose to close down/privatise 47 chronically sick Central Public Sector Undertakings as

reported in the Business Standard dated 19th May, 1992;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of workers employed in these Undertakings;

(d) whether Government are also contemplating some economic package for other sick Public Sector Undertakings; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) and (e) As on 31-3-1991, upto ' which period only the information is available, there are 54 sick industrial central public sector enterprises which are referable *to* BIFR under the provisions of sick Industrial Companies (Special Provisions) Act 1985. The BIFR shall examine these cases for formulation of revival/rehabilitation plans. The National Renewable Fund has also been set up as a Safety Net for protecting the interest of the workers who are likely to be affected due to restructuring of these sick enterprises.

Increase in efficiency and profit of the Central PSU in Maharashtra

660. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL : Will the PRIME MINISTER be pleased *to* state :

(a) the details of the Centra Public Sector Undertakings in Maharashtra in which, capital investment has been decreased during the last three years;

(b) whether the efficiency and profit of these undertakings have increased as a result there of;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government to further increase the efficiency and profits of these underta-

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) There are 28 Central Public Sector Enterprises having their registered office in the State of Maharashtra. The investment and net profit/loss of each of the enterprises during last three years is given in the Annexure. *[See* Appendix CLXV, Annexure No. 9.]

(d) Enterprise specific action is taken by the concerned administrative Ministry/ Department and the enterprise to improve the performance of Central Public Sector Enterprises.

Setting up of new industries in Punjab

661. SHRI IQBAL SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the number and nature of heavy industry likely to be set in Punjab in near future; and

(b) the progress made in this regard so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) 549 Industrial Entrepreneur Memoranda were filed during August, 91 to October, 1992 for setting up of various delicensed industries in Punjab. In addition, 24 Letters of Intent and 9 Industrial Licences have been granted between 1st August, 1991 to 31-10-92 (i.e. since the announcement of the New Industrial Policy). Some of the prominent sectors are : Metallurgical industries, Transportation, Chemicals, Drugs and Pharmaceuticals, Sugar, Fermentation, etc.

(b) Of the 549 Memoranda filed 64 entrepreneurs have already stated their intention to commence commercial production.

Investment in heavy industries

662. DR. JINENDRA KUMAR JAIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :